



## सड़क पर बाजार...



भोपाल। राजधानी की मुख्य सड़कों के फुटपाथों को इस तरह दुकान लगाकर बेचा गया है।

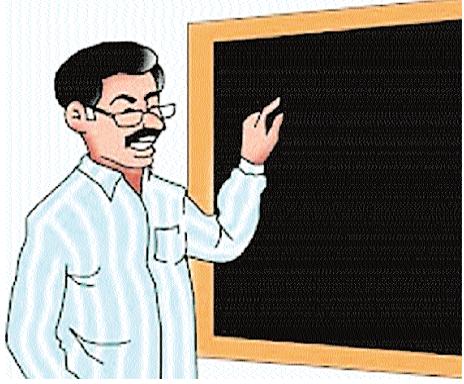
# बीयूः विधि विभाग में शिक्षकों का अभाव, 8 साल से 15 शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

राजधानी स्थित ब्रह्मतङ्ग विश्वविद्यालय विधि विभाग में शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बीयू विधि शिक्षण एवं शोध विभाग में आठ साल से 15 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शासन की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। फाइल आठ साल से विभाग में धूल खा रही है, लेकिन अधिकारियों को फाइल की सुध लेने तक का समय नहीं है। 2017 से अभी तक बीयू से तीन कुलपति विदा हो चुके हैं। चौथे कुलपति के रूप में सुरेश कमार जैन ने भी वित्त विभाग को भौमिका के मंजूरी के लिए स्मरण पत्र भेज दिया है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई सूचना बीयू को नहीं दी गई है। वित्त की मंजूरी के अभाव में विभाग की शैक्षणिक गतिविधियां काफी प्रभावित हो रही हैं। यहां तक कि एलएलएम और बीएएलबी की सीटों में बढ़ती तक नहीं हो सकी है, जिसका नुकसान विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है।

**2017 से अभी तक बीयू से तीन कुलपति विदा हो चुके, चौथे कुलपति ने भी वित्त विभाग को नियुक्ति की मंजूरी के लिए स्मरण पत्र भेजा**

**एलएलएम के लिए पांच पट स्वीकृति**  
बीयू में एलएलएम के लिए पांच पट स्वीकृति किए गए थे। इसमें अभी डॉ मोना पुरोहित विभागाध्यक्ष और अधिकारी और प्रो निरीश आर डेनियल पदस्थ हैं। विभाग को 2017 में पहली बार बीएएलबी और एलएलएम की सीटें बढ़ाने और विद्यार्थियों को बार कार्यसिल आफ इंडिया (बीसीआई) के मापदंड के मुालिक अध्ययन करने के लिए 15 शिक्षकों की जरूरत थी। इसलिए विभाग ने बीयू के तकालीन कुलपति डॉ मुरलीधर तिवारी को पत्र विद्यक सेलफ फायरेंस में 15 शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए स्वीकृति मांगी थी। मामला वित्त से जुड़ा होने के कारण तकालीन कुलपति तिवारी ने फाइल तैयार कराकर उच्च शिक्षा विभाग भेज दिया। फाइल गए हुए आठ साल का समय बीत गया है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने अभी तक फाइल को स्वीकृत या निरस्त करने तक की कोई सूचना नहीं भेजी है।



## मेट्रो ट्रेन की ब्ल्यूलाइन अप्सरा के पास ट्रेस्टिंग

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मेट्रो ट्रेन की ब्ल्यूलाइन में बुधवार को पांचवीं जगह पर ट्रेस्टिंग शुरू की गई। रामधन रोड अप्सरा टॉकीज के पास बैरिकेडिंग कर यहां जमीन की जांच शुरू की गई है। इससे पहले डिपो चौराहा, मिठांगी हॉल, जेके रोड, भद्रभदा रोड पर जांच शुरू की थी। गौरतलब है कि रागिनी से भद्रभदा तक कीरीब 12 किमी लंबाई में मेट्रो की ब्ल्यूलाइन पर काम प्रस्तावित है। 2027 तक ऑरेंज व ब्ल्यूलाइन पर ट्रैफिक शुरू करना है, लेकिन निर्माण में तामात तरह की बाधाएं सामने आ रही हैं। इनके निपटने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है।

**विभाजन का दर्द और भाषाई विस्थापन :** जसवानी का कहना है, 14 अगस्त 1947 सिंधी के लिए एक दर्दनाक दिन था, जब पाकिस्तान का गठन हुआ। विभाजन के दौरान, सिंधी समुदाय को अपनी मातृभूमि से विस्थापित होना पड़ा और लगभग 20 लाख सिंधी हिंदू भारत में शरणार्थी बन गए। सिंधी, जो पहले एक भाषाई राज्य था, अब भारत में सिद्धियों का कोई विशेष भाषाई क्षेत्र नहीं रहा।

**सिंधी भाषा की वर्तमान स्थिति:** आज, शहरों में रहने वाले सिंधी परिवारों में से केवल 15 ही अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। सिंधी लिपि धीरे-धीरे लुम

हो रही है, और युवा पीढ़ी हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता दे रही है। जसवानी का मानना है कि जब तक सिंधी भाषा को रोजगार से नहीं जोड़ा जाता, तब तक इसका उत्थान संभव नहीं है।

**भाषा को रोजगार से जोड़ा जाए:** जसवानी ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सिंधी लिपि को रोजगार से जोड़ने का आहान किया है, जहां सिंधी हिंदुओं की एक बड़ा आबादी है। उन्होंने राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों से सिंधी भाषा के संरक्षण और उत्थान के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है।

**सिंधी भाषा का महत्व:** सिंधी भाषा न केवल एक भाषाई विरासत है, बल्कि यह सिंधी संस्कृति और पहचान की भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका संरक्षण करना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ीयों अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। सिंधी भाषा दिवस पर, हमें सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना चाहिए और इसे एक जीवंत और समृद्ध भाषा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

## होल सेल फायर वर्क्स एसो के आसनदास बने अध्यक्ष

हिरदाराम नगर, दोपहर मेट्रो। मप्र होल सेल फायर वर्क्स के सभी सदस्यों ने एक मत से आसनदास चंदनानी को अध्यक्ष मनोनीची किया। चंदनानी के नाम का फैसला मध्य प्रदेश के होल सेल व्यापारियों के मिटिंग में तिया गया, जिसमें मध्यप्रदेश के कई शहरों से व्यापारी शामिल हुए। मिटिंग में मोहित गोपाली, सुरेश फरावानी, नफीस खान, मनोज जैसवानी, मोहम्मद नफीस प्रमुख रूप से उपस्थित थे। नए अध्यक्ष का स्वागत व्यापारियों ने हार-फूल से किया।



**भूखे को अन्न, प्यासे को पानी सेवा शुरू होगी**  
हिरदाराम नगर, दोपहर मेट्रो।

धार्मिक सामाजिक सेवा संस्था पूर्ण ज्योति सेवा संस्था कई सेवाएं जनकल्पना के लिए आरंभ करने वाली है, जिसकी शुरुआत भूखे को अन्न प्यासे को पानी की सेवा से आरंभ की जाएगी। इस सेवा में गरीब एवं कमज़ोर वर्ग

के लोगों को निशुल्क भोजन प्रदान किसर जाएगा। यह सेवा सेवा संस्था के संस्थापक और शिव महापुराण कथा वाचक मुकेशजी के मार्गदर्शन में की जाएगी। मुकेशजी ने कहा कि अन्न और जल का दाम परम दान है। क्योंकि इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव

## ‘खबरनवीसी आपबीती आंखों देखी’ भेट की...



भोपाल। राजधानी की मुख्य सड़कों के फुटपाथों को इस तरह दुकान लगाकर बेचा गया है।

भोपाल। राजधानी की मुख्य सड़कों के फुटपाथों को इस तरह दुकान लगाकर बेचा गया है।

**सरकारी राशन दुकान के चावल में कीड़े और इलियां, कलेक्टर को जांच के आदेश**

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

भोपाल शहर के शाहजहानाबाद इलाके एक सादी हाल के पास संचालित सरकारी राशन की दुकान से गरीबों को वितरित किए जा रहे चावल में कीड़े और इलियां पाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है।

मप्र मानव अधिकार आयोग ने शाहजहानाबाद इलाके सरकारी राशन के मामले में लिया संज्ञान।

**मप्र मानव अधिकार आयोग ने शाहजहानाबाद इलाके सरकारी राशन के मामले में लिया संज्ञान**

मप्र प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने शाहजहानाबाद इलाके सरकारी राशन के मामले में लिया संज्ञान।

राशन मिल रहा है, वैसा ही बह बांट रहा है। इस घटना से सरकार द्वारा गरीबों को पौष्टिक और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्हें राशन की दुकान से जो चावल मिला है, उसमें बड़ी संख्या में कीड़े और इलियां रेंग रही हैं।

विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को जारी किए आदेश।

## कॉलेजों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगी वर्दी, एक साप्ताह में देना होगा जवाब

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

सरकारी कॉलेजों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बीती वर्दी के लिए विभाग द्वारा वर्दी में बजट प्रदान किया जाता रहा है। इस सत्र 2025-26 में भी वर्दी में नजर आये। उच्च शिक्षा विभाग ने राजधानी सहित प्रदेशभर में सरकारी कॉलेजों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से उनकी आवश्यकता के अनुसार वर्दी में नजर आये। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रेसेस के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि इनके लिए बीती वर्दी का आवश्यकता है, वे कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार दिए गए फॉर्म में एक सप्ताह के अंदर आवेदन प्रस्तुत करें।



## मैपकार्ट: एआई/एमएल आधारित कृषि उपज मॉडलिंग पर हुआ प्रशिक्षण

वैज्ञानिक, रीमोट सेसिंग सेंटर, कृषि विभाग एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मप्र विज्ञान एवं प्रैदीविकीयों परिषद (मैपकार्ट) में एआई



## संपादकीय

# राज्यपाल और सुप्रीम व्यवस्था

**दें** श में कई राज्यों के राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच तनातीनी कोई नई बात नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से यह मसाला चला आ रहा है राज्य सरकारी अक्सर आरोप लगा रही है कि राज्यपाल राजनीतिक भूमिका में नजर आने तगड़े हैं। इसी बीच हाल में तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य और राज्यपालों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान की दिशा में अंधार कदम आना जाना चाहिए। मगर वाकाश ऐसा होगा इसमें अभी कुछ संशय बाकी है। दरअसल शीर्ष अदालत ने एक बार फिर से राज्यपालों की भूमिका स्पष्ट की है। यह फैसला आने वाले वक्त में एक नज़र बनेगा और उम्मीद है कि टकराव के रास्ते से हटकर राज्य सरकारों और राज्यपाल मिलकर काम करेंगे।

तमिलनाडु सरकार को इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि राज्यपाल ने कई विधेयक लंबे समय से रोक रखे थे और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा था। कोई ने इसे अवैध और विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण बताया। इसी तरह का विवाद पिछले साल केरल में भी हुआ था। तब राज्य की

डोमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुडर लगाई थी कि तकालीन राज्यपाल आरिक मोहम्मद खान ने कई बिल दो साल तक लटकाए रखे और फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। देश की शीर्ष अदालत पहले भी कह चुकी है कि राज्यपाल विधानसभा में पारित किसी विधेयक के पास भेजा जायेगा, यह तो आने वाला कल ही बतायेगा, लेकिन यह बात तो सहज समझ में आने वाली है कि जो जहाँ रह रहा है, उसे क्षेत्र-विशेष की भाषा तो आनी ही चाहिए। लेकिन यहीं इस बात की समझ की भी अपेक्षा की जाती है कि हमारा सिविलियन रोज़ी-रोटी के लिए कहीं भी आने-जाने, बसने का अधिकार देश के हर नागरिक को देता है। आसेन्ट-हिमालय सारा भारत देश के सब नागरिकों का है, सबको कहीं भी जाकर बसने का अधिकार है। ऐसे में, क्षेत्र-विशेष की भाषा बोलने की शर्त हर नागरिक के लिए लागू करना शायद उतना व्यावहारिक नहीं होगा, जितना समझा जा रहा है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कोई भाषा न बोल पाने वाला उस भाषा के प्रति अवमानना का भाव रखता है। यहीं इस बात को रेखांकित किया जाना ज़रूरी है कि अपनी भाषा के प्रति लगाव का भाव होना एक स्वाभाविक स्थिति है, अपनी भाषा के प्रति न्याय और सम्मान का भाव होना ही चाहिए, एर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम देश की अन्य भाषाओं के प्रति अवमानना का भाव रखें। देश की सारी भाषाएं हमारी भाषाएं हैं, और हमें सब पर गर्व होना चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभिन्न भाषाओं से समृद्ध हमारे भारत में भाषा के नाम पर विवाद करते हैं। इसका यह अर्थ है कि हम देश की अन्य भाषाओं के प्रति अवमानना का भाव रखते हैं। यह एक हकीकित है कि भाषा की इस राजनीति ने देश के अलग-अलग हिस्सों में अप्रिय स्थितियां पैदा की हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों में भाषा के संस्करणों के बीच हाल में विवाद करते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है।

### ■ विश्वनाथ सचदेव

**म**हाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी को मराठी न बोल पाने की सजा भुगतानी पड़ी। मातृभाषा मराठी के प्रति अतिरिक्त लगाव वाले कुछ मराठी युवाओं ने यह सजा दी थी। उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का संरक्षण प्राप्त था। अब मनसे के नेता राज ठाकरे ने अपने अनुयायीयों से कह दिया है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने की अनिवार्यता के लिए अभियान जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। लोग समझ गये हैं। लोग कितना समझे हैं, और राज्य में मराठी भाषा का उपयोग कितना बढ़ जायेगा, यह तो आने वाला कल ही बतायेगा, लेकिन यह बात तो सहज समझ में आने वाली है कि जो जहाँ रह रहा है, उसे क्षेत्र-विशेष की भाषा तो आनी ही चाहिए। लेकिन यहीं इस बात की समझ की भी अपेक्षा की जाती है कि हमारा सिविलियन रोज़ी-रोटी के लिए कहीं भी आने-जाने, बसने का अधिकार देश के हर नागरिक को देता है। आसेन्ट-हिमालय सारा भारत देश के सब नागरिकों का है, सबको कहीं भी जाकर बसने का अधिकार है। ऐसे में, क्षेत्र-विशेष की भाषा बोलने की शर्त हर नागरिक के लिए लागू करना शायद उतना व्यावहारिक नहीं होगा, जितना समझा जा रहा है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कोई भाषा न बोल पाने वाला उस भाषा के प्रति अवमानना का भाव रखता है। यहीं इस बात को रेखांकित किया जाना ज़रूरी है कि अपनी भाषा के प्रति लगाव का भाव होना एक स्वाभाविक स्थिति है, अपनी भाषा के प्रति न्याय और सम्मान का भाव होना ही चाहिए, एर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम देश की अन्य भाषाओं के प्रति अवमानना का भाव रखें। देश की सारी भाषाएं हमारी भाषाएं हैं, और हमें सब पर गर्व होना चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभिन्न भाषाओं से समृद्ध हमारे भारत में भाषा के नाम पर विवाद खड़े किये जाते हैं। इसका यह अर्थ है कि हम देश की अन्य भाषाओं के प्रति अवमानना का भाव रखते हैं। यह एक हकीकित है कि भाषा की इस राजनीति ने देश के अलग-अलग हिस्सों में अप्रिय स्थितियां पैदा की हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों

में हमने इस राजनीति के दुष्परिणाम देखे हैं। अब भी समय-समय पर इन दुष्परिणामों की चिंगारियां भड़क उठती हैं। बहरहाल, जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है भाषाई आंदोलन यहाँ के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मराठी संस्कृत और भाषा की नाम पर, मराठी अस्मिता की दुर्हाइ देकर राजनीतिक दलों का गठन तक हुआ है। मराठी मानुष के हितों का नाम लेकर राज्य में समय-समय पर आंदोलन होते रहे हैं।

राजनीतिक हितों को साधने की हवस है। यहाँ हितों के बजाय स्वार्थ कहना अधिक उपयुक्त होगा। किसी अफसर को राज्य-विशेष की भाषा बोलनी नहीं आती तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सरेआम थप्पड़ मार दिया जाये। भाषा के हित साधने का यह तरीका अनुचित ही नहीं, आपराधिक भी है। उचित तरीका तो यह है कि हम अपनी भाषा को इतना समृद्ध बनायें कि हर किसी को उसे सीखने, काम में लेने की इच्छा होने लगे। लेकिन हमारे यहाँ



इस संदर्भ में 'मनसे' की हाल की कार्रवाई ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाली है।

हमारे देश में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हुआ है। ये भाषाएं हमारी कमज़ोरी नहीं, ताकत हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी हर भाषा के 'क्लासिकल दर्जा' दिये जाने के बायजूद वह सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इन सब के पीछे भाषा विशेष के प्रति न्याय या सम्मान का भाव नहीं होता, अक्सर राजनीतिक स्वार्थ ही इसका कारण बनते हैं।

स्थित उल्टी है। तमिलनाडु वाले कहते हैं कि हम पर हिंदी थोपी जा रही है, कर्नाटक वालों को सावंजनिक स्थानों पर रहने वाले मराठी भाषा और साहित्य के प्रति कितना आदर-भाव रखते हैं। अपनी भाषा की क्षमता में विश्वास का एक पैमाना यह भी है कि हमारी शिक्षण-संस्थानों में मराठी भाषा में क्या और कितने गर्व से यह कह सकते हैं। यहाँ में सेक्टरों में बदलाव होता है, अर्थात् यहाँ के बायजूद वह सम्मान नहीं दिया जा रहा है; हम में से कितने गर्व से यह कह सकते हैं? किसे बदलाव करने के बायजूद वह सम्मान नहीं होता, अक्सर राजनीतिक स्वार्थ ही इसका कारण बनते हैं।

यदि बात सिर्फ़ प्यार या सम्मान की ही है तो राज ठाकरे की चिंता राज्य में मराठी माध्यम के स्कूलों की संख्या का घटना होती है। साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों की आवश्यकता भी इसका अधिकार है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इन सब के पीछे भाषा विशेष के प्रति न्याय या सम्मान का भाव नहीं होता, अक्सर राजनीतिक स्वार्थ ही इसका कारण बनते हैं।

साधारण भाषा की समृद्धि नहीं है।

गयी है। चिंता इस कमी पर होनी चाहिए। पर कोई नहीं पूछ रहा कि यह सी स्कूल क्यों बंद हो गये। यह तो पूछ जा रहा है कि राज्य में फलों अफसर को मराठी बोलनी क्यों नहीं आती, यह कोई नहीं पूछ रहा कि मराठी माणस प्रस्तुति व्यापार क्षेत्रों को मराठी क्षेत्रों में पढ़ाने संसद नहीं कर रहा है? अपनी भाषा के प्रति प्यार और सम्मान के लिए जल्दी चलाया जा रहा है। अपनी भाषा के प्रति न्याय या सम्मान की चिंता उत्तीर्ण की जाहिए। इन 'बातों' में उत्तीर्ण मराठी में शिक्षा की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा जा रहा है, 'आज मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं और उनकी संपत्ति बेच जा रही है!'

महाराष्ट्र के किसी सरकारी अधिकारी का मराठी बोल पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी यह बात कि महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी भाषा और साहित्य के प्रति कितना आदर-भाव रखते हैं। अपनी भाषा की क्षमता में विश्वास का 'वर्ष 2014-15 में मुंबई महाराष्ट्र व्यापार या गुजराती या बांगला या कन्नड़ माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं?' आज तो स्थिति यह है कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के स्कूल खुल गये हैं और उनके साथ यह जारी हो गया है कि यह 'इंटरनेशनल स्कूल' है। इस इंटरनेशनल का क्या मतलब है, मैं नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूं कि आजादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अंग्रेजी के गुलाम हो गये हैं। यह बीमार मानसिकता है। इससे उत्तरा ही होगा।

साधारण: (ये लेखक के अपने विचार हैं।)

## भगवान महावीर: भारतीय संस्कृति का सूरज







